The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). 60 flats previously built by the Delhi Development Authority in Safdarjung Area have already been allotted by draw of lots. However another 528 flats are under construction in this area. The terms and conditions of sale would be announced in the Press as and when the flats are ready.

Flats for Middle Income Group in Delhi

8829. Shri Shiv Chandika Prasad:

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority propose to build residential flats for middle income group;
- (b) if so, where such flats will be built and by what time they are expected to be sold;
- (c) the types of flats proposed to be built under the scheme; and
- (d) what would be the procedure for the sale of such flats and the conditions of sale?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). Yes. These flats will be offered for allotment to both low and middle income group people and are being constructed in the following development schemes of the Delhi Development Authority:

- Najafgarh Road Industrial Scheme (Tagore Garden).
- (2) Naraina Residential Scheme on Ring Road.
- (3) East of Kailash Residential Scheme (Suraj Parbat).
- (4) Safdarjang Residential Scheme.

The flats are expected to be completed by the end of March, 1968 when they will be disposed off.

(c) and (d). These will be one to three roomed flats and are proposed to be disposed off on outright sale basis. The detailed terms and conditions governing the sale are, however, under consideration of the Delhi Development Authority.

परिवार पेंजन योजना

8830. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों के लिये परिवार पेंशन नियमों, 1964 के अन्तर्गत पहले सात वर्षों के लिये उनकी पेंशन की राशि दुगनी कर दी थी;
- (ख) क्या यह लाभ कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को नहीं दिया जाता जिन कर्मचारियों की मृत्यु यह संशोधन होने से पहले परन्तु इस योजना के लागू होने के बाद हुई थी;
- (ग) ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) क्या ऐसे मामलों में लाभ देने का सरकार का विचार है; ग्रौर
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) परिवार पेन्यन योजना, 1964 को 1-1-1966 से इस सीमा तक उदार बना दिया गया है कि यदि किसी ऐसे धसैनिक सरकारी कमंचारी की जिसकी लगातार सेवा-धविध सात साल से कम न हो सेवा धविध में ही मृत्यु हो जायें तो उसके परिवार को मिलने वाली पेन्यन की रकम उसके धन्तिम समय के मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी परन्तु शतं यह है कि पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन मिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन मिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम मूल आदेशों के प्रधीन सिलने वाली पेन्यन की रकम की ध्रिक से ध्रिष्ठिक